NAVRATAN BHARAT

आर.एन.आई रजि. नं.: RAJBIL/2023/88776, पोस्टल रजि. नं. : श्रीगंगानगर/311/2024-26

नवरतन भारत

नवरतन भारत न्यूज़
NAVRATAN BHARAT NEWS

Navratan Bharat FOLLOW US

अंक 17,वर्ष 3
पृष्ठ 4, मूल्य 5
मंगलवार
हनुमानगढ 21 अप्रैल2026
हिन्दी/अंग्रेजी /साप्ताहिक

प्रधान संपादक लक्ष्मीनारायण स्वामी कार्यालय लक्ष्मीनारायण स्वामी गोविंद सिंह नगर हनुमानगढ़ जं. Email:-info@navratanbharat.com, www:navatanbharat.com,94130-44646

खरीफ-2026 के लिए राजस्थान में बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति जारी

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़, 20 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा गैर-संशोधित **(BG□II, GFM)** बीटी कपास हाइब्रिड की व्यावसायिक खेती के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति **(GEAC)** तथा बीटी कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की औपचारिक अनुमति जारी कर दी गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदित 34 बीज कंपनियाँ राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की आपूर्ति कर सकेंगी।

परीक्षण और क्षेत्रीय अनुमति

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रत्येक बीटी कपास हाइब्रिड के प्रदर्शन का मूल्यांकन कृषि जलवायु क्षेत्रवार एटीसी, एआरएस व केवीके फार्मों पर अनिवार्य परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। 30 अप्रैल 2026 तक बीज कंपनियाँ संयुक्त निदेशक कृषि (ञ्रष्ट), कृषि आयुक्तालय को बीज उपलब्ध करवा सकती हैं, जिसका विभाग निर्धारित मानदंडों के आधार पर परीक्षण शुल्क लेगा। यदि किसी हाइब्रिड पर दो वर्ष से लगातार प्रदर्शन परीक्षण किए जा चुके हैं, तो अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री नरेश कुमार ने बताया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में सफेद मक्खी और कॉटन लीफ कर्ल वायरस **(CLCuD)** के प्रति संवेदनशील बीटी कपास हाइब्रिड की बिक्री पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध रखा गया है, ताकि इन रोगों के प्रकोप को रोका जा सके।

सभी बीज कंपनियाँ अपनी बिक्री क्षेत्रों में कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को त्रि स्तरीय प्रशिक्षण बुवाई पूर्व, फसल वृद्धि तथा कटाई के चरणों में देगी। इसमें बीटी संरचना वाले रिफ्यूज बीज के निर्धारित अनुपात (20' क्षेत्र या पाँच सीमावर्ती कतारें) का पालन, उर्वरक व खाद प्रबंधन, तथा संकीर्ण जैव नियंत्रण तकनीके शामिल हैं।

किसानों को हिंदी में तैयार कृषि पद्धतियों का पैकेज दिया जाएगा, जो बीज पैकेट के साथ प्रत्येक ग्राहक को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है, ताकि ज्ञान आधारित खेती को बढ़ावा मिल सके।

बिक्री नियंत्रण, गुणवत्ता और निगरानी

उन्होंने बताया कि सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीज की बिक्री कीमत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अधिकतम दरों (आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत) से अधिक न हो। प्रत्येक बीज पैकेट पर सत्यापन के लिए एक अद्वितीय त्तग्र कोड तथा वैध संपर्क नंबर अंकित रहना अनिवार्य है।

कंपनियों को जिला वार बिक्री योजना,

डीलर सूची तथा वास्तविक बिक्री की पखवाड़े आधारित रिपोर्ट कृषि संयुक्त निदेशक (विस्तार), जिला परिषद एवं कृषि आयुक्तालय, जयपुर को नियमित रूप से उपलब्ध करवानी होगी, जबकि बीज की मात्रा संरचना और रिफ्यूज बीज की गुणवत्ता पर विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता और पोस्ट रिलीज निगरानी

आयुक्त कृषि ने बताया कि राज्य सरकार ने बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की जिला स्तरीय आपूर्ति में सहकारी क्षेत्र **(KVSS, GSS, FPOs)** को 15-20' आवंटन की प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को बीज आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और संबंधित बीटी कपास कंपनियों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी।

बीज जारी करने के बाद बीटी कपास की निगरानी सम्बद्ध क्षेत्रीय तथा विभागीय ञ्रष्ट की समितियाँ करेंगी, जिनकी रिपोर्ट राज्य स्तर पर विश्लेषण के बाद भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए उपयोग की जाएगी।

हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 01 अवैध देशी पिस्तौल (कट्टा) 07 जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़ जंक्शन 7 जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को अवैध देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के उपनिरीक्षक गुरदेव सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा गश्त और नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर जसजीत सिंह की तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से पुलिस ने निम्नलिखित बरामदगी की:

बरामदगी: 01 अवैध देशी पिस्तौल (कट्टा)एम्युनिशन: 07

जिंदा कारतूस

आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रकरण संख्या 276/2026 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले का आगामी अनुसंधान(**Investigation**) चुंका, उपनिरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

विशेष भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में साक्ष्य और गोपनीय आसूचना संकलन में पुरुषोत्तम और सुरेंद्र सांखला (कांस्टेबल) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आरोपी का विवरण

नाम: जसजीत सिंह पुत्र जसकरण
सिंहजाति: जटसिख (उम्र 23 वर्ष)
निवासी: वार्ड नं. 20, पंजाबी मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन

पुलिस टीम (थाना हनुमानगढ़ जंक्शन) में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे:

गुरदेव सिंह (उपनिरीक्षक)
सुभाषचंद्र (सहायक उपनिरीक्षक)
शंकर लाल (कांस्टेबल नं. 795)
चेतनराम (कांस्टेबल नं. 848)
सर्वजीत सिंह (कांस्टेबल नं. 213, पुलिस चौकी सुरेशिया)

निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति की बैठक आयोजित

- 27 अप्रैल को बड़े आंदोलन का आह्वान, कर्मचारियों व आमजन से भागीदारी की अपील

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़। अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर क्षेत्र की संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली विभाग के निजीकरण के मुद्दे पर गहन चर्चा की गई और आगामी रणनीति तैयार की गई। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए निजीकरण के संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की।बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त समिति के संयोजक अरविंद गढ़वाल ने कहा कि निजीकरण से न केवल कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सभी वर्गों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए।

उन्होंने आगामी 27 अप्रैल को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में व्यापक स्तर पर आंदोलन करने का आह्वान किया। इस आंदोलन में सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं आम नागरिकों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि बिजली जैसे आवश्यक क्षेत्र का निजीकरण जनहित के खिलाफ है। इससे सेवा गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।इस अवसर पर गंगानगर और हनुमानगढ़ से सैकड़ों की संख्या में विद्युत कार्मिकों के आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी तरीके से किया जाएगा, ताकि सरकार तक कर्मचारियों और जनता की आवाज पहुंच सके।बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें अरविंद गढ़वाल, हरीश ढालिया, अनिल श्योराण, कुलदीप शर्मा, संदीप, ओम गोदारा, अनिल चलका, जितेंद्र शेखावत, आत्माराम वर्मा, दीपक सिंधी, दिनेश तथा आईएनटीवीसी से सिमरनजीत सिंह सहित अनेक कर्मचारी व अधिकारी शामिल थे। अंत में सभी ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए निजीकरण के विरोध में संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया।--

भारतीय खाद्य निगम के निर्देशक लोकेश कुमार शर्मा मंडल प्रबंधक रजनीश कुमार,संघ महाप्रबंधक जयपुर पीसी मीणा व सहायक महाप्रबंधक श्रीगंगानगर नीलकमल ने एमएसपी पर हो रही गेहूं की खरीद का मंडी में अवलोकन

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़ टाउन की नई धान मंडी में आज भारतीय खाद्य निगम के निर्देशक लोकेश कुमार शर्मा दिल्ली, मंडल प्रबंधक श्रीगंगानगर रजनीश कुमार,संघ महाप्रबंधक जयपुर पीसी मीणा व सहायक महाप्रबंधक श्रीगंगानगर नीलकमल ने एमएसपी पर हो रही गेहूं की खरीद का मंडी में अवलोकन किया, इस मौके पर हनुमानगढ़ टाउन के फूडग्रेण मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने फूडग्रेण मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में इन सब का स्वागत माला पहनाकर बुके देकर किया । इस मौके पर अध्यक्ष रामलाल किरोड़ीवाल, सचिव दिलीप सिंह ढिल्लों, सहसचिव आशीष गोदारा, कोषाध्यक्ष प्रवीण तलवाडिया,सोहन सिंह, सनी जुनेजा,गगन सोढ़ा, संदीप सिद्धू ने राजस्थानी साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देखकर स्वागत किया । इस मौके पर भारी संख्या में व्यापारी ने भारतीय खाद्य निगम के निर्देशनक लोकेश कुमार को अपनी समस्याओं से अवगत करते हुए एक ज्ञापन सौपा, इस मौके पर सचिव दिलीप सिंह ढिल्लों ने बताया मंडी हनुमानगढ़ टाउन में सरकार द्वारा किसानो की गेहूं खरीद में निम्नाकित परेशानिय उत्पन्न हो रही है जिनका निस्तारण किया जावे -

मंडियों में **FCI** द्वारा **MSP** पर किसानो से 'क' वर्ग कच्चा आढतिया व्यापारी के माध्यम से गेहूं खरीद की जाती है जिसके लिए मंडी के 'क' वर्ग कच्चा आढतिया व्यापारिओं को आढ़त राशि का भुगतान अत्यंत ही कम किया जा रहा है जबकि राज्य राजस्थान के कृषि ऊपज मंडी समितियों द्वारा निर्धारित दर 2.25' है ह्न

राजस्थान में हमारी आढ़त राशि भुगतान **FCI** द्वारा निकटवर्ती पंजाब हरियाणा की अपेक्षा अत्यंत कम भुगतान की जा रही है जबकि काम करने की प्रक्रिया एक समान है

FSD में गेहूं से लदे हुए वाहनों के तौल के दौरान काँटा पर सर्वर में गति अत्यंत धीमी पड़ जाने से तौल प्रक्रिया सम्पन्न होने में 20 से 30 मिनट एक ट्रक के लिए लगते है जिससे गोदाम में ट्रकों की लाइन लग जाने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ह्न **FSD** तक ट्रक आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरते है जिस कारण दुर्घटना का भय बना रहता है ह्न

इस स्थिति के निवारण के लिए **FSD** गोदाम के साथ साथ अन्य भण्डारण केंद्र खोल दिए जावे ताकि तौल तथा मार्ग की सुरक्षा सम्बन्धित समस्या का निवारण हो सके ओर मंडी से बिना मौसमी वर्षा इत्यादि से प्रभावित हुए जल्दी से जल्दी गेहूं का उठाव हो सके ह्न किसानो के खेत में काम करने से तथा आयु के अनुसार उँगलियों तथा आँखों की सही ढंग से स्कैनिंग नही हो पाने से गेहूं तुलाई के समर्थन मूल्य योजना से वंचित रह जाते है ह्न सभी का ध्यान रखते हुए बायोमेट्रिक सत्यापन में देरी अधिक लगने के कारण खरीद केंद्र पर भीड़ अत्यधिक होने से किसानो में आपस में झगड़ा हो जाता है तथा किसान खरीद एजेंसी के कर्मचारियों से झगड़े पर उतारू हो जाते है ओर काम व्यवधान उत्पन्न होता है भुगतान में अत्याधिक विलम्ब होता है ह्न किसानो के मध्य दो तीन बार पूर्व में भी झगड़ा हो चुका है बायोमेट्रिक के लिये बार बार केंद्र पर आना पड़ता है ह्न इसलिए बायोमेट्रिक पद्दति को पूर्णतया गेहूं खरीद प्रक्रिया से हटा दिया जावे ह्न तीव्र गति से मंडी से गेहूं उठाव तथा सुरक्षित भंडारण के लिए अन्य गोदाम गेहूं भण्डारण हेतु खोले जावे ताकि मंडी से अधिक से अधिक दैनिक उठाव की मात्रा में वृद्धि हो तथा सरकारी सरंक्षण में सुरक्षित पहुँच सके ह्न तौल तथा मार्ग आदि की बाधाओं से मुक्ति मिल सके गेहूं खरीद 30 जून 2026 तक किसानो से **MSP** से गेहूं खरीद की जाये,इस बार देरी से शुरू हुई है ओर सरकार द्वारा 31 मई गेहूं खरीद की अंतिम तिथि घोषित की गयी है जिससे किसानो का गेहूं निर्धारित तिथि में बेचान सम्भव नही है तथा किसान सरकार के समर्थन मूल्य स्कीम का लाभ से वंचित हो जायेंगे ह्न गत वर्ष की भांति किसानो का गेहूं खरीद की अंतिम तिथि को 30 जून 2026 तक बढ़ाया जावे और किसानो को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्राप्त हो सके ह्न टाउन मंडी में गत वर्ष लगभग 30 लाख गेहूं के कट्टे **FCI** द्वारा खरीद किया गया था जिसमे इस बार सरसों के स्थान पर गेहूं की बुवाई की गयी है जिससे गेहूं की पैदावार अधिक होने के कारण मंडी टाउन में 40 लाख गेहूं कट्टो की खरीद की सम्भावनाओं को देखते हुए वर्तमान में बारदाना का अभाव है ह्न पुराने बारदाना के स्थान पर नया बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ह्न पुराने बारदाना को उल्टा करके गेहूं भरने के बाद सिलाई सम्भव नही है ह्न इसलिए नया बारदाना उपलब्ध करवाए ह्न **FCI** के गोदाम **FSD** तक गेहूं से लदे भारी वाहनो के लिए ॥ञ्ज को जो मार्ग स्वीकृत करके दिया हुआ है वह अत्यंत कष्टदायक तथा आवासीय क्षेत्र से होकर निकलता है जिसमे से ट्रक के मुड़ने के दौरान 90डीग्री के मोड़ पर ट्रक दुर्घटना ग्रस्त होने की सम्भावना अधिक है ओर बड़ी दुर्घटना होने से जान माल का नुक्सान सम्भव है को देखते हुए अन्य सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था करवाए जावे उन्होंने बताया हनुमानगढ़ टाउन में सरकार द्वारा किसानो की गेहूं खरीद में के पश्चात मंडी से भण्डारण के लिए **FCI FSD** के गोदाम में मार्ग की परेशानी होने के कारण तथा कांटे के सर्वर इत्यादि में तकनीकी परेशानी के कारण निम्न गोदामों को भण्डारण हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवाने का श्रम करे ताकि मंडी से किसानो को असुविधा का सामना नही करना पड़े -

ABP वेयरहाउस , टिब्बी रोड हनुमानगढ़ टाउन 1.5 लाख कट्टा,मरुधरा वेयरहाउस , टिब्बी रोड हनुमानगढ़ टाउन 1.5 लाख कट्टा,प्रीति वेयरहाउस , कोहला हनुमानगढ़ टाउन 2.0 लाख कट्टा की भण्डारण क्षमता है ।इस मौके पर गुरजीवन सिंह,प्रभज्योत,गिन्नी, मोंटू सधा, विपिन गोयल,लवप्रीत सिंह, अमन धालीवाल, नरोत्तम सिंगला आदि व्यापारी उपस्थित रहे ।

संपादकीय

सड़कों को न बनने दें 'मौत' का गलियारा

मुद्दा
अवधेश कुमार

देश में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या अब एक सामान्य बात नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और कानून के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ताजा निर्देश केवल कानूनी आदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी हैं। यह चेतावनी उस सिस्टम के लिए है, जिसने सड़कों को सुरक्षित बनाने के बजाय कई जगहों पर उन्हें मौत का गलियारा बनने दिया। अदालत ने साफ कहा है कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे "खतरे के गलियारे" नहीं बनने चाहिए। यह टिप्पणी यूं ही नहीं आई। इसके पीछे वे दर्दनाक हादसे हैं, जिनमें एक ही दिन में दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और तेलंगाना की हालिया घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी सड़कों पर खतरा केवल वाहन चलाने की गलती से नहीं, बल्कि अव्यवस्थित सिस्टम और लापरवाही से भी पैदा होता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि देश की कुल सड़क लंबाई में नेशनल हाईवे का हिस्सा महज 2% है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30% है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। हाईवे, जो तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए बनाए जाते हैं, वही सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, वे इस समस्या के मूल कारणों को संबोधित करते हैं। भारी और कमर्शियल वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर रोक, अवैध ढाबों और निर्माणों को हटाने का आदेश, एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए निगरानी। ये सभी कदम न केवल जरूरी हैं, बल्कि लंबे समय से लंबित भी थे। खासकर हाईवे के किनारे अवैध निर्माण और बिना योजना के विकसित ढाबे, अक्सर हादसों का बड़ा कारण बनते हैं, लेकिन भारत में समस्या आदेशों की कमी नहीं, उनके क्रियान्वयन की है। पहले भी सड़क सुरक्षा को लेकर कई गाइडलाइंस और नियम बनाए गए, लेकिन उनका असर सीमित ही रहा। कारण साफ है, जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और जवाबदेही का अभाव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन इन सभी की भूमिकाएं स्पष्ट हैं, लेकिन जब हादसा होता है, तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। अदालत ने इस बार टास्क फोर्स और एसओपी के जरिए इस कमी को दूर करने की कोशिश की है। केवल सिस्टम लगाना पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग और नियमित निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। सड़क सुरक्षा को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानना भी अधूरा दृष्टिकोण है। इसमें आम नागरिकों और वाहन चालकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक नियमों का पालन, ओवरस्पीडिंग से बचाव और सड़क पर अनुशासन, ये सभी पहलू हादसों को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब सिस्टम ही अव्यवस्थित हो, तो व्यक्तिगत सावधानी भी कई बार पर्याप्त नहीं होती। हाईवे केवल विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व भी हैं। अंततः, सड़कें केवल दूरी कम करने का माध्यम नहीं होतीं, वे जीवन से जुड़ी होती हैं। अगर इन सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा हो जाए, तो विकास का पूरा मॉडल ही सवालों के घेरे में आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए और सड़क सुरक्षा को नीतिगत प्राथमिकता बनाया जाए, क्योंकि हर हादसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक परिवार की अपूरणीय क्षति होती है और इसे रोकना ही असली जिम्मेदारी है।

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह पहला अवसर है, जब कोई विधेयक पारित होने से लोकसभा में वंचित रह गया। 1996 से महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण देने का मामला लटका हुआ है और विरोधी किसी न किसी बहाने इसमें अड़चन डालते आ रहे हैं। किसी का तर्क कुछ भी हो, निष्कर्ष यही है, वही प्रक्रिया फिर दोहराई गई है। अब इसमें गुणात्मक अंतर यह है कि मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 33% महिलाओं के आरक्षण का कानून संसद द्वारा पारित करवा लिया है। इसलिए उसको लागू तो होना है, किंतु अब विधेयक के गिर जाने से 2029 लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हो सकता।

महिला आरक्षण की फिर वही परिणति

लगभग 12 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह पहला अवसर है, जब कोई विधेयक पारित होने से लोकसभा में वंचित रह गया। 1996 से महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण देने का मामला लटका हुआ है और विरोधी किसी न किसी बहाने इसमें अड़चन डालते आ रहे हैं। किसी का तर्क कुछ भी हो, निष्कर्ष यही है, वही प्रक्रिया फिर दोहराई गई है। अब इसमें गुणात्मक अंतर यह है कि मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 33% महिलाओं के आरक्षण का कानून संसद द्वारा पारित करवा लिया है। इसलिए उसको लागू तो होना है, किंतु अब विधेयक के गिर जाने से 2029 लोकसभा चुनाव में यह लागू नहीं हो सकता।

इसके लिए हमें 2034 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दरअसल, 2023 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि अगली जनगणना और फिर परिसीमन हो जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा। तब अनुमान यह था कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया 2029 तक पूरी हो चुकी होगी, इसलिए इसे लागू करने में समस्या नहीं होगी। चूंकि यह पूरी नहीं हुई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे संविधान संशोधन के जरिए तत्काल लागू करने का रास्ता चुना। पूरे प्रकरण का कठोर सच यह है कि इन तीनों विधेयकों में ऐसा कुछ नहीं था, जिसको आशंका की दृष्टि से देखा जाए और जिसका इस सीमा तक विरोध हो कि काले झंडे और काले बिल्ले तक पार्टियां व सांसद लगा लें। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान करता था। इनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें थीं। दूसरा,परिसीमन विधेयक, 2026 नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान करता था। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए था। विपक्ष का मुख्य विरोध पहले विधेयक से था।

वस्तुतः संसद का विशेष सत्र आरंभ होने के पहले ही विपक्ष ने अविश्वसनीय रूप से विरोधी रुख अपनाकर अपने संसदीय व्यवहार का संकेत दे दिया था। विपक्ष के सभी नेताओं ने, जिनमें महिला सांसद भी शामिल हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन संबंधी विधेयकों का जैसा विरोध किया, उसमें साफ हो गया कि इसका पारित होना संभव नहीं है। भाजपा के मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं से बात करनी शुरू की। स्वयं प्रधानमंत्री ने दो पोस्ट से अपील की। इसके पहले वे अपने भाषण में अपील कर चुके थे कि श्रेय आप लोग ले लीजिए, लेकिन महिला आरक्षण में बाधा मत बनिए, लेकिन विपक्ष पहले से मन बनकर बैठा था। उन्होंने अपनी अपील में लिखा कि अपने घर में मां-बहन, बेटी -पत्नी सबको देखिए और उनके अधिकार के लिए विचार कर मतदान करिए। निष्पक्ष होकर विवेक, तथ्य और तर्क के साथ विचार करने वालों का निष्कर्ष है कि पूरा विरोध एकपक्षीय अतिवाद से ग्रस्त रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसे देश विरोधी और देश को बांटने वाला विधेयक तक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये देश

का भूगोल बदलना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। इससे अधिक अतिवादी वक्तव्य और कुछ नहीं हो सकता। अगर इरादा विधेयक पर बहस कर इसमें उचित संशोधन करना हो तो आपके भाषण में उससे संबंधित सुझाव होते हैं। सरकार की राजनीतिक आलोचना में समस्या नहीं है, किंतु पूरी बहस सामान्य आलोचना ही नहीं, विधेयक के विषय वस्तु से भी काफी दूर चला गया था। प्रश्न उठाया जा रहा था कि आखिर 850 सीटों का आपका आधार क्या है? इसी तरह के दक्षिण के राज्यों को इसमें नजरअंदाज किया जा रहा? बजट सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत शुरू की तो बताया होगा कि हर राज्य की 50% लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें बढ़ाने का फार्मूला तय हुआ है। आज परिसीमन हो तो लोकसभा एवं विधानसभाओं की कितनी सीटें बढ़ सकतीं हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से 120 हो रही हैं तो तमिलनाडु की 39 से 59। इसी तरह अन्य राज्यों के भी विवरण दिए गए। हंगामा इस पर भी था कि 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया गया? गृह मंत्री का उत्तर था कि 2011 की जनगणना का आधार बनाते तो तमिलनाडु की सीट केवल 49 होती। यहां दो बातें समझने की हैं। एक, वर्तमान 543 सीटों में 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? 2023 में जब विधेयक पारित हुआ तभी उसमें जनगणना और परिसीमन का प्रावधान था। विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? 1996 से उसके विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि आपसी बातचीत में नेता बोलते थे कि 543 में से 33% महिलाओं को मिल गया तो अनेक पुरुष नेताओं को घर बैठ जाना पड़ेगा और राजनीति का नाश हो जाएगा। पिछड़ों के आरक्षण आदि का बहाना बनाया गया, तो पुराने अनुभवों का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने रास्ता निकाला कि 543 सीटें जस की तस रहें और बढ़ी 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, सहमति हुई तभी 2023 में कानून बन सका।

आज यह तर्क देने वाले अपनी सरकारों में इसके लिए तैयार नहीं थे। 1996 में विरोध करने वाले उस संयुक्त मोर्चा सरकार के साथी थे तो 2008 से 2010 तक विरोध करने वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथी। इनमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ समय तक जनता दल यूनाइटेड अग्रणी रहे। दूसरे दलों के सांसद भी साथ देते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 और 1999 में महिला आरक्षण विधेयक चलाया किंतु आम सहमति नहीं बन सकी। 2010 में राज्यसभा में भाजपा के समर्थन से विधेयक पारित हुआ, किंतु उनके साथी दलों ने विरोध किया और लोकसभा में पारित करना मुश्किल था। दूसरे, हर 10 वर्ष पर संविधान लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का प्रावधान करता है। 1971 तक नियमित होता रहा। 1976 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संशोधन कर 2001 तक लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटें न बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। अगर दल वाकई महिला आरक्षण के पक्ष में होते तो विरोध जताते हुए कुछ संशोधन डालकर पारित कर देते। सीटों की संख्या की लिखित गारंटी के प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि आप विधेयक पारित करते हैं तो हम नया संशोधन सीटों की संख्या डालकर पेश करने को तैयार हैं।

वास्तव में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों को दिखाना था कि हम संसद में नरेंद्र मोदी सरकार को पराजित कर सकते हैं। किसी नेता ने महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर अफसोस प्रकट नहीं किया। महिलाओं के आरक्षण पर विरोधियों का जो रुख हमने 1996 से देखा, लगभग वही अलग रूपों में फिर संसद में था और इसी की परिणति विधेयक के गिरने के रूप में सामने आई।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आधी दुनिया

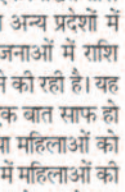

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

सत्ता में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक औसत से बहुत दूर

संसद में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का बिल गिरने के साथ ही देश में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से महिलाओं से माफी मांगी है तो दूसरी ओर विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत और सरकार की हार बताया है। हालांकि विपक्ष यह भी कह रहा है कि उनका विरोध सीटों के परिसीमन से अधिक है। खैर, यह अलग बहस का विषय हो सकता है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में हम दुनिया के देशों से अभी काफी पीछे चल रहे हैं। दुनिया के 190 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमारे देश का स्थान 147वां आता है। दुनिया के देशों में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक स्तर औसत 27.5 फीसदी है। 30 महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं, जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हम महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी की बात कर रहे हैं, वहीं इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं, जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हालिया चुनावों में 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 19 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणा पत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या अन्य प्रदेशों में लखपति दीदी या इसी तरह के नाम से मिलती-जुलती योजनाओं में राशि उपलब्ध कराने की रणनीति महिला वोटों को अपनी ओर करने की रही है। यह दूसरी बात है कि इसका लाभ किस पार्टी को अधिक मिला। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहें या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें, पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बढ़ नहीं पाई है। 2009 की 15वीं लोकसभा के पहले तक तो हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी आगे नहीं पहुंचा था। 15वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो भले ही महिला आरक्षण बिल का अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस व अन्य विपक्षियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी विपक्ष में मतदान किया पर लोकसभा और राज्य सभा में टीएमसी दल की महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो उसकी भागीदारी 14.3 प्रतिशत और बीजेपी की भागीदारी 12.9 प्रतिशत है। अन्य दलों की भी कमोबेश यही स्थिति है। राज्यों कक की बात करें तो इस समय देश में सर्वाधिक महिला सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा में हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सदस्यों में 21.1 प्रतिशत महिला सदस्य हैं।

त्रिपुरा में 15 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। बाकी देश के अन्य राज्यों में 15 प्रतिशत महिलाएं भी विधानसभा की सदस्य नहीं हैं। नागालैंड देश का ऐसा प्रदेश है, जहां सबसे कम महिला सदस्य हैं। कर्नाटक जैसे राज्य में भी पांच प्रतिशत से कम महिला विधानसभा सदस्य हैं। इससे यह तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि जब तक संवैधानिक बाध्यता नहीं होगी, तब तक महिलाओं की भागीदारी लाख प्रयासों के बावजूद नहीं बढ़ने वाली है। इसके लिए एक सीमा तक सीटों का आरक्षण करना ही होगा। इसका जीता-जागता उदाहरण पंचायतीराज व स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं, जहां महिलाओं की सीटें आरक्षित होने से आज तस्वीर ही बदल गई है। यदि महिलाओं की सत्ता में सहभागिता बढ़ानी है तो महिला सीटों का आरक्षण करना ही होगा। राजनीतिक दलों को आपसी आग्रह दुराग्रहों से हटकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गैरसरकारी संगठनों को भी इस दिशा में देश में माहौल बनाना चाहिए। यह अवश्य है कि आरक्षण की सीमा आपसी समन्वय व विचार-विमर्श से सर्वसम्मति से तय होता है तो यह बेहतर लोकतांत्रिक परंपरा होगी। यह साफ है कि अब समय आ गया है जब महिलाओं की हिस्सेदारी तय होनी ही चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

प्रसन्न रहने की शुरुआत घर से हो

संकलित
दर्शन

महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसन्न रहने की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। हम बाहर तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन घर में अकारण क्रोध से भरे रहते हैं। सभी लोग, खासतौर पर युवा इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें घर में भी प्रसन्न रहना है। युवाओं को यह बात याद रहे, इसलिए एक नया मंत्र दे रहा हूं। वे घर और परिवार में भी शांति रखें। कई लोग बाहर से घर में आते ही क्रोधित हो जाते हैं। वे अकारण गुस्सा कर घर वालों को मायूस कर देते हैं। यह हत्या कर देने जैसा अपराध है। मुश्किल यह है कि ये लोग अपनी कमी को मानते भी नहीं। कम से कम वे यह मान लें कि उसमें यह कमी है तो कभी न कभी वह कमी दूर भी की जा सकती है। लंका में कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई रोगी है। परिणाम सबके सामने है। जो माने ही नहीं कि अस्वस्थ है, वह स्वस्थ कैसे हो सकता है? एक और मंत्र याद रखें-छोटी-मोटी बातों को अनदेखा करें। व्यर्थ विवाद में मत उलझें। बात-बात में उलझने की आदत से अशांति ही पैदा होती है। सच्ची प्रसन्नता चाहिए तो इधर-उधर की बातें सुनना ही छोड़ दें। अस्तित्व के संगीत को सुनने की कोशिश करें। याद रखें, जिसे प्रसन्न रहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे दुखी ही रहना है, उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ लोगों को प्रसन्न रहना ही नहीं है। वे परेशान और दुखी होने के बहाने खोजते रहते हैं। इस आदत को बदलने की कोशिश ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए।

एक लकड़ी का कटोरा

संकलित
प्रेरणा

एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहु-बेटे के यहां शहर रहने गया। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका चार वर्षीया पोता एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। बहु-बेटे कुछ दिनों तक तो ये सब सहन करते रहे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिता जी आप यहां पर बैठ कर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वहीं अकेले में बैठ कर अपना भोजन करने लगा, यहां तक की उनके खाने-पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठ कर खाना खाते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता, और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले, उस छोटे बालक को उसके माता-पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा- तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सकें, और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता-पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आँखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आये, और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत की धरोहरों को और निखारने की जरूरत

दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने इसकी शुरुआत की थी। जब इस दिवस को यूनेस्को ने मंजूरी दी थी, तब से यह दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की संभाल करना और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना भी है। हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी धरोहरें हैं जो दुनिया के आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें मुख्यतः अजंता एलोरा की गुफाएं, दिल्ली का कुतुब मीनार व आगरा का ताजमहल इत्यादि शामिल हैं। और भी ऐसी बहुत सी धरोहरें हैं। भारत की धरोहरों को और निखारने की जरूरत भी है। ये धरोहरें देश की सभ्यता-संस्कृति की पहचान करवाती हैं। - मिलिंद जोशी, बिलासपुर

ट्रेंड

महिला आरक्षण कानून

डीएमके, कांग्रेस और टीएमसी ने संसद में 33% महिला आरक्षण कानून को पारित नहीं होने दिया, लेकिन हम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अवश्य प्रदान करेंगे।
- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

बंगाल में दयनीय स्थिति

बंगाल में हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एसिड अटैक, बाल अपराध, बलात्कार, डकैती, लूट और चोरी की घटनाएं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हो रही हैं। "मा, मा और मिट्टी" की बात करने वाली ममता दीदी ने इन स्थितियों को बेहद दयनीय बना दिया है।
- जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

तमिल पहचान की रक्षा

परिसीमन आयोग द्वारा संसद में तमिलनाडु, दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व को कम करने का एक स्पष्ट प्रयास था। हमने संसद में इसे रोका और भारत की अवधारणा पर इस हमले को विफल कर दिया। इंडिया अलायंस हमेशा तमिल पहचान की रक्षा करेगा।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

बेटियों की हार

विपक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि बेटियों की हार लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? देश की महिलाओं की हार हुई है, उनका सम्मान और आत्मसम्मान छिन गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत कैसे कह सकता है?
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

उ. कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी

उत्तर कोरिया ने रविवार को समुद्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया एवं जापान ने यह जानकारी दी। ये मिसाइल ऐसे समय में दागी गई हैं जब कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने परमाणु हथियार बनाने के उत्तर कोरिया के प्रयासों में 'बेहद गंभीर'' प्रगति की चेतावनी दी थी। दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' (जेसीएस) ने बताया कि उत्तर कोरिया के सिनपो क्षेत्र से दागी गई ये मिसाइलें देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र की दिशा में करीब 140 किलोमीटर (87 मील) तक गईं। जेसीएस ने कहा कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की उकसाने वाली हर प्रकार की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है और वह अमेरिका एवं जापान के साथ सूचनाओं का निकटता से आदान-प्रदान कर रहा है। दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की आपात बैठक में चिंता जताई और उससे इन्हें तुरंत रोकने का आग्रह किया। ये प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के भारत और वियतनाम की यात्रा के लिए रवाना होने से कुछ घंटे पहले किए गए।

ऑफ बीट

क्या माउथवॉश हृदय के लिए हानिकारक होता है?

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि माउथवॉश से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है और हृदय की सेहत को नुकसान हो सकता है। कुछ वीडियो के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउथवॉश मुंह के उन अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जो हृदय और रक्त-प्रणाली के लिए जरूरी होते हैं। यह सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है लेकिन आपको अभी अपना माउथवॉश फेंकने की जरूरत नहीं है। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये सभी मिलकर एक संतुलित और विविध प्रकार के 'माइक्रोबायोम' बनाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया की बढ़त को रोकते हैं, सामान्य 'मेटाबॉलिज्म' में मदद करते हैं और मुंह व शरीर की कुल सेहत को बेहतर बनाते हैं। इन बैक्टीरिया का एक अहम काम है हमारे भोजन (खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों) में मौजूद नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलना। जब हम नाइट्राइट निगलते हैं, तो शरीर इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह प्रक्रिया नाइट्रेट-नाइट्राइट-नाइट्रिक ऑक्साइड प्रक्रिया (या एंटरोसैलिवरी प्रक्रिया) कहलाती है। यह एक उदाहरण है कि बैक्टीरिया कैसे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

विशेष : पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल

अपनी पृथ्वी को बनाएं स्वच्छ-सुरक्षित और सुंदर

हमारी पृथ्वी स्वच्छ, सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र स्वच्छ, संतुलित और सुरक्षित रहे। बच्चो, कुछ छोटे-छोटे कदम उठाकर तुम भी हमारी पृथ्वी के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो।

अवेयरनेस

शिखर चंद जैन

बच्चो, इस पृथ्वी पर मनुष्य, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, हम सभी रहते हैं। पृथ्वी हमारे घर की तरह है। पृथ्वी की रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को 'अर्थ डे' यानी 'पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है। इसे 'इंटरनेशनल मदर अर्थ-डे' के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' निर्धारित की गई है। इसका मतलब है, हम सब पृथ्वीवासी के रूप में अपनी शक्तियों और सूझबूझ का प्रयोग करें और अपनी पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाएं।

हम बच्चे क्या कर सकते हैं

तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी की सुरक्षा हम बच्चे भला कैसे कर सकते हैं? यहां यह समझना होगा, तुम्हें अकेले पूरी पृथ्वी की रक्षा नहीं करनी है। बस अपने हिस्से का काम करना है। जब सभी लोग अपने-अपने हिस्से का काम करेंगे तो पृथ्वी को प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ और हरी-भरी रखने की दिशा में बड़े बदलाव होने लगेंगे। हमारी पृथ्वी हरी-भरी, स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त हो जाएगी।

खूब लगाओ पेड़-पौधे

बच्चो, पेड़-पौधे, घने जंगल और वनस्पतियों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यह तो तुम जानते ही हो कि हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाईऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़-पौधे इसके विपरीत कार्बन डाईऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए भी पेड़-पौधे और जंगल बहुत जरूरी हैं। तो आज ही ठान लो कि तुम पेड़-पौधों से सच्ची दोस्ती करोगे और इसे निभाओगे। तुम खूब पेड़-पौधे लगाओगे, उसकी देखभाल करोगे। यह हमारी पृथ्वी और हमारे लिए बहुत जरूरी है।

प्लास्टिक को कहो बाय-बाय

आज के समय में प्लास्टिक हमारी पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। धरती को स्वच्छ-सुरक्षित बनाने की दिशा में हमारा मुकाबला 'प्लास्टिक दानव' से भी है। हमारी कोशिश हो कि हम कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें ताकि हमारी धरती, समुद्र की मछलियां, घरेलू और जंगली जानवरों के साथ-साथ पेड़-पौधे और हम इंसान भी इसके दुष्प्रभावों से बचें।

कचरे का सही डिब्बा चुनो

यहां-वहां कचरा फेंकने और इसका सही निस्तारण न करने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होने के साथ-साथ हमारी पृथ्वी के लिए भी काफी नुकसानदायक है। इसलिए हमें समझदारी से कचरे का निस्तारण करना चाहिए। नीला डस्टबिन सूखे कचरे के लिए और हरा डस्टबिन गीले कचरे के लिए यूज करना चाहिए। अगर हम कचरा सही जगह डालेंगे, तो हमारी धरती साफ-सुथरी बनी रहेगी।

ऊर्जा का करो संरक्षण

ऊर्जा सीमित संसाधन है। इसका बेतहाशा इस्तेमाल हमारी पृथ्वी और पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली की बचत कर हम अपनी पृथ्वी को बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। इसलिए कमरे से बाहर जाते समय या जब जरूरत न हो, लाइट, पंखे और बिजली के अन्य उपकरण बंद करने की आदत डालें।

पशु-पक्षियों का सहारा बनो

पशु-पक्षी हों या कीट-पतंग या फिर कोई भी अन्य जीव, सभी पृथ्वी के लिए आवश्यक हैं। ये हमारे ईको सिस्टम को बैलेंस्ड रखने में सहायक हैं। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी को खुशहाल रखने के लिए भी इन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। गर्मी के दिनों में अपनी छत या बालकनी पर मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना जरूर रखो। *

मत करो पानी की बर्बादी

'जल ही जीवन है' ये स्लोगन तो तुमने सुना होगा। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को अपने दैनिक उपयोग के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। पानी बहुत ही अनमोल है, इसकी बर्बादी रोकना जरूरी है। हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ब्रश करते समय नल बंद रखना और नहाने के लिए शॉवर के बजाय बाल्टी-मग का इस्तेमाल करना, ऐसी छोटी-छोटी आदतें अगर हम सभी अपनाएं, तो बहुत सारा पानी बचाया जा सकेगा।

बच्चों को स्टोरी या नॉलेज से जुड़ी किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में किताब लिखकर, सबको चौंकाया, देश-दुनिया में प्रसिद्ध हुए। हम तुम्हें ऐसे ही कुछ प्रतिभावान बच्चों और उनकी प्रकाशित किताबों के बारे में बता रहे हैं।

टैलेंटेड-क्रिएटिव ये नन्हे राइटर

भारत में कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ने की उम्र में खुद ही एक से बढ़कर एक शानदार किताबें लिख डालीं। छोटी उम्र में ही किताबें लिखकर इन बच्चों ने सभी को हैरान कर दिया है। वर्ल्ड बुक डे (23 अप्रैल) के मौके पर जानो, ऐसे ही कुछ टैलेंटेड नन्हे राइटर्स के बारे में।

वाणी रावल

हरियाणा की वाणी रावल ने 10 साल की उम्र में 'कैथी' 23 डेज ऑफ क्रिसमस' और 'कैथी इज कॉलिंगः फाइव एलिमेंट्स ऑफ क्रिसमस' नामक किताबें लिखीं। किताबों की ये सीरीज लिखकर वाणी ने दुनिया की सबसे कम उम्र की 'सीरीज राइटर' होने का गौरव हासिल किया। वाणी का नाम 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड', 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड', 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स', 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज है। *

अभिजिता गुप्ता

उत्तर प्रदेश की अभिजिता गुप्ता ने 7 साल की उम्र में अपनी पहली किताब 'हैप्पीनेस ऑल अराउंड' लिखी। वह 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका मानी गई है। वह अब तक 3 किताबें लिख चुकी है। 2020 में अभिजिता ने कहानी और कविता की पुस्तक की सबसे कम उम्र की लेखिका होने का रिकॉर्ड बनाया, जिसे 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभिजिता की कुछ प्रमुख किताबें हैं- 'श्योरली सरटेन', 'द बिगिन विद द लिटिल थिंग्स', 'मार्क ऑफ द कीपरः वेल ऑफ लाइट'। अभिजिता को 'ग्लोबल चाइल्ड प्रॉडिजी अवॉर्ड 2022' से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहां यह भी जानो कि अभिजिता हिंदी साहित्य की महान विभूति राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की परपोती है। *

अयान गोगोई गोहेन

असम के अयान गोगोई गोहेन ने मात्र 4 साल की उम्र में अपनी पहली किताब 'हनीकॉम्ब' लिखी थी। उसे 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' द्वारा भारत का सबसे कम उम्र का लेखक घोषित किया गया है। अयान दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखकों में से एक है। वर्ष 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड विजेता अयान ने 'बंबलबी' और 'लाइफ लेसंस फ्रॉम द फोर-लेग्ड मोंक' जैसी किताबें भी लिखी हैं। अयान दुनिया के शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं की सूची में भी शामिल हो चुका है। *

पर्यावरण संरक्षण की कहानियां

बच्चो, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है धरती का पर्यावरण शुद्ध रहे। पर्यावरण तभी शुद्ध रहेगा, जब हम सभी मिलकर इसको संरक्षित करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर बाल साहित्यकार डॉ. नागेश पांडेय 'संजय' ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से कथाओं का संकलन 'पर्यावरण संरक्षण की कहानियां' तैयार किया है। इस किताब में देश के जाने-माने 15 बाल साहित्यकारों की कहानियां संकलित की गई हैं। बच्चो, इस किताब की कहानियों में तुम्हें प्रकृति के नए-नए रंग देखने को मिलेंगे, जो तुम्हारे भीतर पर्यावरण के प्रति प्रेम जगाएंगे। इस संकलन की कहानियों में कहीं देव नदी गंगा अपनी मदद के लिए पुकार रही है, तो कहीं पर 'अलईतारा' के रूप में श्रमदान का महत्व बताया गया है। इस संकलन की एक कहानी 'बिन मौसम' तुम्हें झूमते हुए वृक्षों की छांव में ले जाएगी। कहानी 'पानी नहीं' बताती है पानी की फिजूल खर्ची से कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? किताब की हर कहानी कोई ना कोई संदेश देती है, तुम्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। कहानियों के साथ छपे सुंदर चित्र इस किताब के आकर्षण को बढ़ाते हैं। किताब का आवरण बहुत ही मोहक है। एक खास बात यह है कि इसमें बने चित्रों में तुम्हें रंग भरने का मौका मिलेगा। *

किताब: पर्यावरण संरक्षण की कहानियां, **संपादक:** डॉ. नागेश पांडेय 'संजय'
मूल्य: 230 रुपए, **प्रकाशक:** बुनियादी साहित्य प्रकाशन, लखनऊ

कल्पना करो धरती, सौरमंडल में तीसरी कक्षा से दूर चौथी कक्षा में आ जाए तो क्या होगा? यही होगा, सारे प्राणियों का जीवन घोर संकट में आ जाएगा। इसलिए जरूरी है, हम अपनी आदतें सुधारें, पर्यावरण संरक्षित करें। बच्चो, यह कहानी सौरमंडल में धरती के निश्चित स्थान की महत्ता बताती है।

जब धरती ने जगह बदलने की ठानी

इलस्ट्रेशन

आज विद्यालय में विशेष चहल-पहल थी। स्कूल का प्रांगण हरे और नीले गुब्बारों से सजा था। मंच पर लगे एक बैनर पर बड़े अक्षरों में लिखा था-पृथ्वी दिवस। प्रधानाचार्य जी ने मंच पर आकर माइक से घोषणा की, 'आज कक्षा सात के विद्यार्थी एक विशेष नाटक प्रस्तुत करेंगे-जब धरती ने जगह बदलने की ठानी।'

तभी मंच पर परदा खुला। मंच के बीचों-बीच नीले-हरे वस्त्र पहने एक बच्ची खड़ी थी। वह धरती बनी थी। उसके चारों ओर रुई से बने बादल और चमकीले तारे सजे थे। धरती उदास स्वर में बोली, 'मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूं। धुआं, प्रदूषण, बढ़ते तापमान से। मैं सौरमंडल में सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर यानी तीसरी कक्षा में हूं। क्यों न मैं चौथी कक्षा में आ जाऊं। वहां कुछ ठंडक मिलेगी।'

पास में मौजूद चंद्रमा घबराए स्वर में बोला, 'ऐसा मत करो धरती बहन! इससे सौरमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा।'

तभी अलग-अलग वेशभूषा में कुछ बच्चे मंच पर आए। एक बच्चा पेंग्विन बना था। उसने घबराते हुए कहा, 'धरती मां, अगर आप दूर चली गईं तो यहां बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ जाएगी। समुद्र जम सकते हैं। हमें भोजन कहां मिलेगा?'

हाथी बना हुआ बच्चा बोला, 'जंगलों में धूप कम हुई तो पेड़-पौधे कैसे उगेंगे, बढ़ेंगे? हम क्या खाएंगे?'

एक बच्ची जो किसान बनी थी, बोली, 'हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी।'

समुद्री नीले वस्त्रों में एक बच्चा, जो व्हेल बना था, बोला, 'पृथ्वी बहन तुम्हारे दूर जाने से समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटे का रूप बदल जाएगा।'

तभी एक बाल वैज्ञानिक मंच पर आया। उसने चार्ट दिखाते हुए कहा, 'धरती का सूर्य से निश्चित दूरी पर तीसरी कक्षा में होना ही, इस पर जीवन के लिए आदर्श स्थिति है। यदि पृथ्वी चौथी कक्षा में चली गई तो यह अत्यधिक ठंडी और बंजर हो सकती है, जैसे मंगल ग्रह। और यदि धरती सूरज के पास यानी दूसरी कक्षा में आ जाए तो तपने लगेगी, जैसे शुक्र ग्रह।'

सामने बैठे दर्शक छात्र, ध्यान से सभी बातें सुन रहे थे। धरती ने दुःखी स्वर में कहा, 'पर मेरा बुखार कौन समझेगा? ग्लोबल वार्मिंग मुझे बीमार कर रही है।'

तभी छोटे-छोटे बच्चे पौधे लेकर मंच पर आ गए। एक ने कहा, 'गलती हमारी है। धरती आप अपनी जगह मत बदलें। हम बदलेंगे अपने आपको।'

दूसरे ने कहा, 'हम पेड़ लगाएंगे!'

तीसरे ने कहा, 'हम बिजली बचाएंगे!'

चौथे ने कहा, 'हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे!'

पांचवें ने कहा, 'हम हर दिन पृथ्वी दिवस मनाएंगे!'

धरती बनी बच्ची कुछ क्षण चुप रही फिर मुस्कुराते हुए बोली, 'यदि तुम सचमुच अपना व्यवहार बदलोगे, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।'

अंतिम दृश्य में सभी बच्चे हाथों में हाथ डालकर बोले, 'धरती हमारी है, हम इसके रखवाले हैं! हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे।'

परदा गिरा। नाटक खत्म हो गया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य जी मंच पर आकर बोले, 'बच्चो, अभी जो तुमने देखा, यह केवल नाटक नहीं है। यह सच्चाई है। धरती अपनी कक्षा नहीं बदल सकती, पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं।' आज स्कूल में पृथ्वी दिवस पर केवल एक कार्यक्रम नहीं हुआ था, यहां संकल्प लिया गया था, पृथ्वी को बचाने का। *

कविता

राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव

पृथ्वी कितनी प्यारी है!

पृथ्वी कितनी प्यारी है!
सभी ग्रहों से न्यारी है।
हम सबकी जीवनदायी,
हितकारी उपकारी है।
खेत और खलिहान यहां,
वन-उपवन, मैदान यहां।
नदियां ताल समंदर हैं,
खनिजों की हैं खान यहां।
तितली भौंरे सुमन यहां,
पंछी पर्वत पवन यहां।
जल, थल, बादल, नील गगन,
जीवन, भोजन, वसन यहां।
लेकिन वन कटते जाते,
नए शहर बसते जाते।
मिट्टी रेत खनिज पानी,
दिन-प्रतिदिन घटते जाते।
अब हम लें जिम्मेदारी,
और न दोहन हो भारी।
हम सब मिलकर यत्न करें,
बची रहे पृथ्वी प्यारी।

बूझो तो जानें

1. नीला पानी, हरी है घास,
सबके लिए हूं मैं तो खास।
इंसान, पशु और पक्षी सारे,
रहते हैं मेरे ही सहारे।

2. सिर पर ऊपर नीला अंबर,
पैरों के नीचे मिट्टी सुंदर।
पहाड़, नदी और जंगल घने,
सब कुछ हैं मुझसे ही बने।

-शिवानी छाया

उत्तर : पृथ्वी

जीके क्विज-201

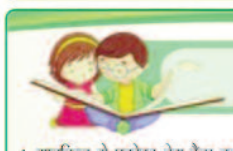

1. साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है?
2. हाल में ही बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
3. रूपा बायर किस खेल से संबंधित है?
4. आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं?
5. श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है?
6. तेनालीरामा किस राजा के दरबारी विद्वान थे?
7. विश्व की सबसे गहरी झील कौन-सी है?
8. भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं?
9. भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है?
10. किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?

बच्चो, जीके क्विज-201 का उत्तर बालभूमि के अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। सही जवाब देने वाले बच्चों के नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे। तुम अपने जवाब हमें **balbhoomihb@gmail.com** पर मेल कर सकते हो।

जीके क्विज-200 का उत्तर : 1. रोपड़ (पंजाब), 2. भारत, 3. अकबर और हेमू, 4. मिथुन मन्हास, 5. विशाखदत्त, 6. हेग(नीदरलैंड), 7. बुध, 8. विटामिन ए, 9. बी.आर. आंबेडकर, 10. राजस्थान

जीके क्विज-200 का सही उत्तर देने वाले : साकेत-दुर्ग, कबीर-हिसार, अनन्या-राजनांदगांव, कविश-रायपुर, सौम्या-रायगढ़, ऊर्जस्वी-सारंगढ़ बिलाईगढ़, तमन्ना-कोरबा, अक्षित-बिलासपुर, सुमित-रोहतक, हर्ष-बालोद

अंतर बताओ

बच्चो, यहां पार्क में पिकनिक मना रहे भालू और खरगोश के दो चित्र दिए गए हैं। एक जैसे दिखने वाले इन चित्रों में सात अंतर हैं। तुम पांच मिनट में सभी सात अंतर ढूंढ कर बताओ।

उत्तर: 1.भालू तरबूज के बजाय सैंडविच खा रहा है। 2.खरगोश ने टोपी नहीं पहनी है। 3.बेंच पर बिल्ली के बजाय एक पक्षी बैठा हुआ दिख रहा है। 4.पेड़ के नीचे दो तितलियां उड़ रही हैं। 5.भालू के बगल में रखा बास्केट गायब है। 6.भालू की छोटी-सी पूंछ दिख रही है। 7.फूलों वाले गमले की जगह पर बास्केट रखा हुआ है।

लेफ्ट-राइट बताओ

बच्चो, यहां दी गई तस्वीर में कुछ क्लाउन फिश लेफ्ट की तरफ घूमी हुई है, तो कुछ राइट की तरफ। तुम्हें गिनकर दिए गए बॉक्स में लिखना है कि कितनी क्लाउन फिश लेफ्ट की तरफ घूमी हुई है, कितनी राइट की तरफ?

LEFT

RIGHT

उत्तर: ??????????????

एफसीआई निदेशक ने हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी का किया निरीक्षण

-गेहूं खरीद व्यवस्था, बायोमैट्रिक प्रक्रिया व बारदाने की समस्या पर व्यापारियों ने रखी मांग

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्यालय के निदेशक लोकेश कुमार शर्मा सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं खरीद प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीद व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की तथा बायोमैट्रिक प्रणाली की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों और संघ पदाधिकारियों ने निदेशक के समक्ष अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मपाल जिन्दल (डिम्पल), व्यापार संघ अध्यक्ष पदम जैन, व्यापारी नेता प्यारेलाल बंसल और मनमोहन गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में गेहूं की खरीद प्रक्रिया में कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं।

व्यापारियों ने विशेष रूप से एफसीआई के सभी गोदामों को शीघ्र खुलवाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सीमित गोदामों के कारण ट्रकों की लोडिंग और अनलोडिंग की गति प्रभावित हो रही है, जिससे मंडी में जाम जैसी स्थिति बन रही है और किसानों व व्यापारियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि सभी गोदाम संचालित किए जाएं तो गेहूं उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। मौके पर ही लोकेश शर्मा ने गोदामों को खुलवाने के लिए क्षेत्र प्रबंधक एफसीआई को निर्देशित किया।

इसके अलावा बारदाने (जूट बैग) की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। व्यापारियों ने बताया कि सरकार द्वारा बारदाने का मानक वजन 580 ग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि वास्तविकता में यह बैग सूखने के बाद लगभग 400 ग्राम ही रह जाता है। इस अंतर के कारण व्यापारियों और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि या तो वजन मानक में संशोधन किया जाए या -फिर इस नुकसान की भरपाई के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

बायोमैट्रिक प्रक्रिया को लेकर भी व्यापारियों ने कुछ तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कई बार तकनीकी खामियों के कारण किसानों को अनावश्यक रूप से इंतजार करना पड़ता है, जिससे खरीद प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

इस पर एफसीआई निदेशक लोकेश कुमार शर्मा ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सभी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बारदाने के वजन सहित अन्य मुद्दे सरकार की नीति से जुड़े हुए हैं और इस संबंध में उच्च स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

निरीक्षण के अंत में निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि मंडी में व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें और किसानों व व्यापारियों को राहत मिल सके।

परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज का भव्य आयोजन

-सुन्दरकांड पाठ के साथ 47 प्रतिभाओं का सम्मान, समाज में शिक्षा व संस्कारों का संदेश

नवरतन भारत न्यूज़

हनुमानगढ़। ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित गौड़ ब्राह्मण धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धा और आस्था के साथ सुन्दरकांड पाठ का आयोजन किया गया, वहीं समाज की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया।कार्यक्रम डॉ. एमपी शर्मा की अध्यक्षता में समपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही और पूरे आयोजन का माहौल धार्मिक एवं उत्साहपूर्ण बना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे सुन्दरकांड पाठ के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के गुणगान करते हुए भक्ति भाव से पाठ में भाग लिया। यह पाठ परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली के धर्मशाला परिसर में पहुंचने के साथ ही पूर्ण हुआ। इस दौरान पूरे परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर आयोजन को सफल बनाया।

सुन्दरकांड पाठ के समापन के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 47 होनहार प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इन प्रतिभाओं ने शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर समाज का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में विशेष रूप से आईएएस में चयनित गरिमा शर्मा को सम्मानित किया गया, जिनकी उपलब्धि समाज के लिए प्रेरणादायक मानी गई।

इसके अलावा सीएमएचओ अखिलेश शर्मा, वैद्य तीर्थ कुमार, सांवरमल शर्मा, मदनलाल शर्मा, रजीलाल शर्मा, सुरेश शर्मा, वैभव दाधीच, केशव शर्मा, तमन्ना, सिद्धांत जोशी, पलक गौड़, आकाश शर्मा, संदीप शर्मा, सौरभ कौशिक, प्रणय, नेहा शर्मा, विशाल शर्मा, नवनीत शर्मा, अभय शर्मा, हिमांशु कौशिक, दीपक पारीक, श्रुति पारीक, मनोज शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, निपुण शर्मा, युगदीप ऐरी, पुण्या शर्मा, डॉ. भारत भूषण शर्मा, ओजस्वी सारस्वत, दुर्लभ जोशी, मधुबाला, शिवा, संजीव, प्रेम कुमार, हिमांशु महर्षि, हरीराम सारस्वत, अजय लाल चतुर्वेदी, कृष्ण जोशी, कृष्ण शर्मा, दिवांशु, सुरेश कुमार, यश भारद्वाज, आशीष गौतम और अरविंद सहित कुल 47 प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

समारोह में वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में शिक्षा और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को इन प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। साथ ही, शिक्षा के साथ संस्कारों का महत्व भी बताया गया और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठजन एवं पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन समिति के सदस्यों ने सभी अतिथियों और प्रतिभाओं का स्वागत करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि समाज की प्रतिभाओं को उचित मंच मिल सके और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे।

समापन के अवसर पर सभी प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। उक्त आयोजन को सफल बनाने में यादवेन्द्र शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, प्रदीप ऐरी, आशीष पारीक, भारत भूषण कौशिक, प्रहलाद शर्मा, जसवीर शर्मा, महेन्द्र शर्मा, हरीश शर्मा, इंजी हंसराज शर्मा, गिरीराज शर्मा, द्वारका प्रसाद, झमनलाल पाईवाल, लेखराम जोशी, कुंज बिहारी महर्षि, सूर्यप्रकाश जोशी, पवन पारीक, बनवारीलाल पारीक, शिवनारायण सारस्वत, पंडित सुरेश लाल सहित अन्य समाज के लोगों का भरपुर सहयोग रहा।

जन्मदिन पर मिला सुनने की शक्ति का वरदान: जयपुर में 4 साल की बच्ची का सफल ऑपरेशन

नवरतन भारत न्यूज़

जयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चिकित्सा जगत के साथ-साथ मानवता का भी दिल जीत लिया है। एक 4 साल की मासूम बच्ची, जो दुनिया की आवाजों से अनजान थी, उसे उसके जन्मदिन पर 'सुनने की शक्ति' का सबसे अनमोल उपहार मिला है।

अनोखा संयोग: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह (स्स्र) अस्पताल में आज बारां निवासी 4 वर्षीय तनिष्का का सफल कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया। खास बात यह रही कि आज ही तनिष्का का जन्मदिन भी है। डॉक्टरों के सफल प्रयास से अब यह बच्ची सुनने की नई दुनिया में कदम रखेगी।

पूरी तरह निःशुल्क इलाज: ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि यह जटिल ऑपरेशन मुख्यमंत्री द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है।

विशेषज्ञों की टीम:

इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में निम्नलिखित विशेषज्ञ शामिल रहे:एनटी नेतृत्व डॉ. पवन सिंघल (विभागाध्यक्ष) सहयोगी डॉक्टर्स डॉ. आभा कपूर, डॉ. भवानी, डॉ. अन्वेषा निश्चेतन विभाग प्रो. डॉ. सोनाली बेनीवाल नर्सिंग स्टाफ मंजू और रितुभविष्य की नई उम्मीद:

'तनिष्का अब न केवल सुन पाएगी, बल्कि सही स्पीच थेरेपी के साथ बोलना भी सीख सकेगी। उसके जन्मदिन पर इससे बेहतर उपहार और कुछ नहीं हो सकता था। '– डॉ. पवन सिंघल, ईएनटी विभागाध्यक्ष

तनिष्का के परिवार के चेहरे पर छाई यह मुस्कान प्रदेश की उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की कर्मठता का प्रतीक है। आज का दिन तनिष्का के जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है।

भाईचारा टाइपिस्ट यूनियन के प्रधान बने गौरव मेहता, फूल-मालाओं से हुआ स्वागत

नवरतन भारत न्यूज़

ऐलनाबाद, 20 अप्रैल (रमेश भार्गव) शहर की भाईचारा टाइपिस्ट यूनियन की एक आवश्यक बैठक आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के लगभग सभी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और आपसी सहमति से नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से गौरव मेहता को भाईचारा टाइपिस्ट यूनियन का प्रधान नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर उपस्थित सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया तथा लड्डू बांटकर इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाया।

नवनियुक्त प्रधान गौरव मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि वे सभी सदस्यों के विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन की एकता, पारदर्शिता और सदस्यों के हितों की रक्षा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने सभी साथियों से सहयोग की अपील करते हुए यूनियन को और मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर विजय फुटेला, नवीन शर्मा, राकेश पोहडका, हरविंदर जीवन नगर, राजवीर किरोड़ीवाल, रवि चावरिया, छिंद्रपाल, मंगत कुमार, पवन गर्वा, महेंद्र पोपली, राकेश कुमथला, बृजलाल सैनी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करें, कमियों को चिन्हित कर करें सुधार : सुराणा

जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, मिली एयर स्ट्राइक की सूचना, तुरंत मौके पर पहुंचे जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी निश्चय प्रसाद एम, एडीएम अर्पिता सोनी सहित एबुलेंस आवश्यक सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा, पुलिस व मेडिकल टीम आदि ने हताहतों को पहुंचाया अस्पताल, दिया उपचार, ब्लैक आउट का भी किया अभ्यास, जिला कलक्टर सुराणा व एसपी निश्चय प्रसाद एम ने रिस्पॉन्स टाइम की समीक्षा कर दिए निर्देश

चूरू, 20 अप्रैल। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में सोमवार को जिला मुख्यालय पर आपातकालीन स्थितियों पर प्रभावी नियंत्राण तथा आपात सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम परीक्षण के उद्देश्य से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

मॉक ड्रिल के बाद जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने विभिन्न विभागों के रेस्पॉन्स टाइम की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास जारी रखा जाए तथा कमियों को चिन्हित कर उनमें सुधार किया जाए।

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपनी सेवाओं के लिए सदैव तैयार रहें तथा रिस्पॉन्स टाइम के न्यूनतम स्तर तक के लिए मुस्तैद रहें। सभी अधिकारी अपने संसाधनों व आवश्यक गतिविधियों के बारे में समुचित जानकारी रखें। आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बरती जाने वाली ऐहतियात के बारे में जागरूक रहें तथा नियमित अभ्यास में लाएं।

जिला कलक्टर ने बताया कि मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम व आमजन की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना था। इस प्रकार की मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सुदृढ़ करने में सहायक होती हैं तथा इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। मॉक ड्रिल के दौरान सामने आई कमियों का विश्लेषण कर शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से त्वरित रिस्पॉन्स व बेहतर तालमेल से आपदा की स्थिति में प्रभावी नियंत्राण संभव है। उन्होंने पुलिस बलों को सुरक्षा गतिविधियों का कड़ाई से पालन करने तथा सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय विद्यालय में एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल के दौरान जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय विद्यालय में एयर स्ट्राइक की सूचना मिली तो कंट्रोल रूम से तुरंत सभी अधिकारियों को सूचना दी गई और सभी अधिकारी, एंबुलेंस, पुलिस, नागरिक सुरक्षा बल, अग्निशमन, स्वयंसेवक आदि तुरंत मौके पर पहुंचें। इसके साथ ही सायरन के माध्यम से क्षेत्रा के लोगों को भी जानकारी सावधानियां बरतने की जानकारी दी। इस दौरान सभी सेवाओं के अधिकारी समयबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचे तथा दुर्घटना में हताहतों को नागरिक सुरक्षा बलों, पुलिस जवानों, स्वयंसेवकों, मेडिकल टीम व स्वयंसेवकों आदि के माध्यम से एंबुलेंस से जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डीबी जनरल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार किया गया।

घटना स्थल पर हताहतों के उनकी गंभीरता के अनुसार चिन्हित करते हुए मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने सामान्य घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार, गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल व मृतकों को शव निपटान का अभ्यास किया।

एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि एयर स्ट्राइक में 05 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 14 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं 05 व्यक्ति सामान्य घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देते हुए मेडिकल सहायता दी गई।

इसी क्रम में सोमवार शाम को ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस दौरान शाम 07.15 बजे से जिला मुख्यालय पर सायरन की आवाज के साथ ही ब्लैकआउट किया गया तथा विद्युत आपूर्ति बंद कर आपात स्थिति में आवश्यक सेवाओं के संचालन की क्षमता को परखा गया। ब्लैकआउट में आपातकालीन परिस्थितियों में जनसहभागिता एवं व्यवस्थाओं की तत्परता का आकलन किया गया।

तुरंत पहुंचें अधिकारी व आवश्यक सेवाओं के प्रतिनिधि

एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी निश्चय प्रसाद एम, एडीएम अर्पिता सोनी, एएसपी सुनील कुमार, एसडीएम सुनील कुमार, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, एपीआरओ मनीष कुमार, तहसीलदार अशोक गोरा, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, सानिवि एसई पंकज यादव, डिस्कॉम एसई आरपी वर्मा, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, एसीपी नरेश दुहानिया, एसजेईडी डीडी नगेन्द्र सिंह, क्यूआरटी, एंबुलेंस सेवा, मेडिकल टीम, अग्निशमन, सिविल डिफेंस टीम, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सहित सभी अधिकारी, कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचें और आपातकालीन अभ्यास

गांव धोतड की गौशाला में चेक वितरण समारोह 22 अप्रैल को

नवरतन भारत न्यूज़

ऐलनाबाद,रानियां 20 अप्रैल :(रमेश भार्गव)

गांव धोतड की श्री अमरनाथ गौशाला में 22 अप्रैल बुधवार को प्रातः 10:00 बजे चारा अनुदान राशि का चेक वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा हलका प्रतिनिधि शीशपाल कंबोज ने बताया कि कार्यक्रम में बुवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह रानियां हल्के की 38 गौशालाओं को सवा दो करोड रुपए के चेक वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि विधायक कपूर सिंह रानियां विधानसभा हलके के प्रभारी भी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस वर्ष पहले भी 3 मार्च को सोनीपत के भटगांव की धर्मार्थ गौशाला में प्रदेश की 602 गौशालो को चारा अनुदान राशि के रूप में 68 करोड़ 34 लाख 30295 के चेक वितरित किए थे, जिसमें सिरसा जिला की 138 गौशालाओं को 10 करोड़ 19 लाख 70 हजार 960 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी।इसी कड़ी में प्रदेश सरकार वर्ष की दूसरी तिमाही में एक बार फिर प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालयों को चारा अनुदान राशि वितरित कर रही है। रानियां हल्का में गौशाला प्रबंधको को घर द्वार पर जाकर अनुदान राशि के चेक वितरित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर बुवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह की ड्यूटी लगाई है, जो की 22 अप्रैल बुधवार को प्रातः 10:00 बजे गांव धोतड की श्री अमरनाथ गौशाला में पहुंचकर हल्के की सभी पंजीकृत 38 गौशाला को सवा दो करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगे।

शीशपाल कंबोज ने बताया कि रानियां की श्री गौशाला को 1218540 रुपए और श्री गोपाल नंदीशाला को 483000 रुपए, गांव चक्का की श्री गौशाला को 1139880 रुपए, गांव बनी की श्री कृष्ण चंद्र गौशाला को 1809180 रुपए, गांव केहरवाला की श्री गौ सेवा समिति को 1036380 रुपए, गांव पनीवाला मोटा की श्री कृष्ण गौशाला को 1063060 रुपए, गांव खारिया की बाबा मूंगा नाथ गौशाला को 1395640 रुपए, गांव भूना की श्री भूना गौशाला धाम समिति को 415380 रुपए, गांव सादेवाला की श्री गौशाला को 785680 रुपए और 500000 रुपए, गांव बालासर की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला और नंदीशाला सेवा समिति को 680340 रुपए, गांव बहिया की श्री कृष्ण गौशाला को 611340 रुपए, गांव बचेर की श्री कृष्ण आदर्श गौशाला को 606280 रुपए, गांव नथोर की श्री श्री 1008 बाबा मोती नाथ गौशाला को 568100 रुपए, गांव मंगालिया की श्री राधा कृष्ण गौशाला को 204240 रुपए, गांव फतेहपुरिया की श्री श्याम गौशाला को 163300 रुपए, गांव पंजुआना की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदी शाला को 498180 रुपए, गांव मंगाला की बाबा भूमन शाह जी गौशाला को 344540 रुपए, गांव खुइयां नेपालपुर की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदी शाला को 233680 रुपए, गांव साहूवाला प्रथम की श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति को 356040 रुपए, गांव जोधपुरिया की श्री सोमनाथ गौशाला को 680800 रुपए, गांव घोड़ेवाली की श्री कृष्ण गौशाला को 444360 रुपए, गांव भभूर की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदी शाला को 336720 रुपए, गांव बुर्जभंगू की श्री हरी राम गौशाला को 385020 रुपए,गांव वनसुधार की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला एवं नंदी शाला को 486680 रुपए, ग्राम शेखूपुरिया की श्री कृष्ण गौशाला को 378580 रुपए, गांव ओटू की श्री राधा कृष्ण गौशाला को 304980 रुपए, गांव मैंनाखेड़ा की श्री कृष्ण गौशाला को 464600 रुपए, गांव गदिडा की श्री बांके बिहारी गौशाला को 489900 रुपए, गांव धोतड की श्री अमरनाथ गौशाला को 767280 रुपए, गांव खाजाखेड़ा की श्री कृष्ण गौशाला को 319240 रुपए, गांव कुसर की श्री राधा कृष्ण गौशाला को 561200 रुपए, गांव ढूड़ियावाली की श्री गोपाल गौशाला को 518420 रुपए, गांव श्री जीवननगर की सतगुरु जगजीत सिंह गौशाला को 125120 रुपए, गांव संतनगर की नामधारी गौशाला टिब्बा फॉर्म को 521640 रुपए, गांव मम्मडखेड़ा की श्री दुर्गा गौशाला को 444820 रुपए की चारा अनुदान राशि के चेक वितरित किए जाएंगे।

इस अवसर पर रानियां गौशाला के प्रधान एवं उद्योगपति संदीप मित्तल, मार्केट कमेटी रानियां के पूर्व वाइस चेयरमैन संजय सिंगला, तरण क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ तरसेम सिंह, हरियाणा राज्य गौशाला संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पोपली, अरिहंत फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेश जैन, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित जिंदल, युवा अग्रवाल सम्मेलन के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल, मार्केट कमेटी रानियां के निदेशक विक्की गुप्ता और राजेंद्र थोरी, पूर्व सरपंच राजेंद्र कंबोज, अनिल शर्मा, ब्लॉक समिति के सदस्य गोविंद कंबोज और सोनू कंबोज, राजू सिंगला भी उपस्थित थे।

स्वामी प्रकाशक लक्ष्मी नारायण स्वामी एवं मुद्रक विकास शर्मा के द्वारा शांति सरोज प्रिंटर्स अंबेडकर कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ से मुद्रित एवं कार्यालय नवरतन भारत वार्ड नंबर 17 गोविंद सिंह नगर हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान335512 से प्रकाशित एवं प्रसारित संपादक लक्ष्मी नारायण स्वामी, वाद- विवाद का न्यायिक क्षेत्र हनुमानगढ़ होगा RNI NO RAJBIL/2023/88776 www.navratanbharat.com,email:›info@navratanbharat.com,